प्रसार भारती

भारतीय प्रसारण निगम

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

22.11.2024 / प्रादेशिक समाचार / 09.20 बजे

सीपीएस मामला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के छह मुख्य संसदीय सचिवों को हटाने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की है। इस पर आज सुनवाई होगी। राज्य सरकार की तरफ से मामले की पैरवी कपिल सिब्बल करेंगे। हाईकोर्ट ने बीते 13 नवंबर को सीपीएस एक्ट–2006 को अमान्य करार देते हुए छह मुख्य संसदीय सचिवों को तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद मुख्य संसदीय सचिवों के तौर पर छह विधायकों को मिल रही सुविधाएं खत्म कर दी गई थीं। राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने बताया कि प्रदेश में मुख्य संसदीय सचिवों को मंत्रियों जैसी सुविधा नहीं दी गई थी और न ही वे मंत्रियों की तरह कार्य करते थे। इसी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है।

राजेश धर्माणी

तकनीकी शिक्षा, नगर नियोजन और आवास मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि प्रदेश सरकार खेलों व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है और खेल ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है। राजेश धर्माणी कल सुंदरनगर में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग महिला चैंपियनशिप के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि में भी बढ़ोतरी की है। इस अवसर पर राजेश धर्माणी ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया। ओवरऑल चैंपियनशिप में आरकेएमवी शिमला ने पहला, एमएलएसएम सुंदरनगर ने दूसरा और सेंट बीड्स कॉलेज शिमला ने तीसरा स्थान हासिल किया।

मन की बात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 24 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश–विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 116वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नम्बर 1 8 0 0–1 1–7 8 0 0 पर कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। माइगॉव, नमो एप पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने की आज अंतिम तिथि है। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा।

ईपीएफओ–यूएएन

केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आधार से जुडी ओटीपी के जरिए कर्मचारियों का यूनिवर्सल अकाउंट नम्बर सक्रिय रहे। इसका उद्देश्य अधिकाधिक नियोक्ताओं और कर्मचारियों को इस वर्ष के बजट में घोषित नियोजन–आधारित आर्थिक प्रोत्सा हन योजना का लाभ दिलाना है। पहले चरण में, नियोक्ताओं को इस महीने की 30 तारीख तक सभी कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नम्बइर सक्रिय करना होगा। दूसरे चरण में, तस्वीर और बायोमीट्रिक विवरण की पुष्टि की जाएगी। इससे कर्मचारियों को पैसा निकालने या ट्रांसफर करने की ऑनलाईन सुविधा मिलेगी और भविष्य निधि खातों का प्रभावी प्रबंधन किया जा सकेगा।

मौसम

प्रदेश के न्यूनतम तापमान में लगातार आ रही गिरावट से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। जनजातीय इलाकों में न्यूनतम तापमान माइनस में चला हुआ है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर सुबह–शाम घना कोहरा छा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई है। जबकि अन्य भागों में मौसम साफ बना रहेगा। 24 से 27 नवंबर तक प्रदेशभर में मौसम के शूष्क रहने के आसार हैं। प्रदेश में पिछले लंबे समय से बारिश न होने से कृषि व बागवानी पर प्रतिकूल असर देखा जा रहा है।

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर.....

आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है।

अमर उजाला की सुर्खी है–बारिश और बर्फबारी न होने से बिजली उत्पादन प्रभावित, शिमला–धर्मशाला से भी ठंडी ऊना, मंडी, बिलासपुर की रातें। पंजाब केसरी के शब्द हैं–शिमला में एक ने ठंड से तोड़ा दम। हिमाचल दस्तक लिखता है–पहाड़ों से ज्यादा ठंडे हुए प्रदेश के मैदानी इलाके। दैनिक भास्कर का शीर्षक है–51 दिन से सूखा, अभी बारिश–बर्फबारी के नहीं आसार।

आपका फैसला ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है–ठियोग में 86 करोड़ से स्थापित होगी वाइनरी। जबकि दिव्य हिमाचल के शब्द हैं–सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने एचपीएमसी को दिया लाइसेंस। दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है–ठियोग के नजदीक पराला में वाइनरी स्थापित करने की कवायद तेज।

दैनिक जागरण ने प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश को सुर्खी दी है–तौर–तरीके सुधारे स्वास्थ्य विभाग–पीएचसी में स्टाफिंग पैटर्न संबंधी आदेश का पालन न होने पर स्वास्थ्य सचिव पर की टिप्पणी। वहीं दैनिक भास्कर का शीर्षक है–हाईकोर्ट के आदेशों के पालन के लिए सरकार को अपने तौर–तरीके सुधारने की आवश्यता।

शिक्षा विभाग में भी अनुबंध अवधि को मिली सिनियोरिटी शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है–हिमाचल के शिक्षा विभाग में अनुबंध अवधि को वरिष्ठता देने का आदेश जारी।

सीपीएस मामले पर अमर उजाला के शब्द हैं–सुप्रीम कोर्ट में छह याचिकाएं दायर, सुनवाई आज। पंजाब केसरी के अनुसार–सीपीएस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दिल्ली पहुंचे सुक्खू।